

प्रेस नोट

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ अनुसूची की मुख्य विशेषताएं

कोई टैरिफ वृद्धि नहीं

सस्ती बिजली

हरित बिजली

1) कोई टैरिफ वृद्धि नहीं :

- आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ अनुसूची, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी, इसके साथ संलग्न है।
- सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मौजूदा टैरिफ ढांचे में कोई वृद्धि करने के लिए कोई सही कारण नहीं है।

2) दिल्ली के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली:

- दिल्ली के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर बिजली की आपूर्ति करने के प्रयास में - बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी और टीपीडीडीएल ने दादरी-I, अंता गैस, औरैया गैस, दादरी गैस, फरक्का, कहलगांव-I और ऊंचाहार-I। जैसे विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से लगभग 1050 मेगावाट महंगी बिजली के समर्पण का अनुरोध किया है। इस संबंध में, डीईआरसी ने इस मामले को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष भी उठाया है और उनसे दिल्ली के पोर्टफोलियो से महंगी बिजली का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया है।
- बीआरपीएल ने विभिन्न बिजली आपूर्ति व्यापारियों के साथ एक समझौता किया है जिसमें बीआरपीएल परिधि पर 24x7 बिजली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध है।
- एपीएम गैस, जो सस्ता ईंधन है, वर्तमान में जीटीपीएस और पीपीएस-I के लिए उपलब्ध नहीं है जो कि जीओएनसीटीडी (GoNCTD) गैस आधारित संयंत्र हैं। तदनुसार, दिल्ली सरकार संयंत्र महंगे आर-एलएनजी ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं और उपभोक्ता महंगी बिजली से लदे हुए हैं। जीओएनसीटीडी (GoNCTD) ने इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) भारत सरकार के साथ उठाया है और उनसे दिल्ली के उपभोक्ताओं तथा दिल्ली के पर्यावरण के हित में दिल्ली गैस आधारित संयंत्रों के लिए एपीएम गैस की उपलब्धता बहाल करने का अनुरोध किया है।

3) हरित दिल्ली:

- डीईआरसी ने "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सौर योजना" (MMKABSY) के लिए अधिकतम टैरिफ को मंजूरी दे दी है जो किसानों, विकासकर्ताओं और डिस्काम्स के बीच एक बैक-टू-बैक समझौता है। इससे किसानों



को अपनी कृषि भूमि पर सौर पैनल स्थापित करने और जीओएनसीटीडी (GoNCTD) द्वारा अनुमोदित मासिक आय अर्जित करने में सक्षम करेगा।

- डीईआरसी ने "हरित बिजली" को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत आभासी और समूह नेट मीटरिंग मोड डेवलपर्स के लिए सर्विस लाइन सह विकास (एसएलडी) और नेटवर्क विस्तार शुल्क की छूट प्रदान की है।
- दिल्ली के उपभोक्ताओं को हरित बिजली की आपूर्ति करने के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ने डीईआरसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न समझौते किए हैं। इसके अलावा, बीआरपीएल ने हाल ही में एक ऐसी परियोजना को इंडो-जर्मन सोलर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में मालवीय नगर के शिवालिक ग्रिड में चार्जिंग सुविधा से लैस 100 kW पीक सोलर फोटो वोल्टाइक प्लांट और 466 kWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को स्थापित किया है। यह परियोजना जर्मन विकास एजेंसी "जीआईजेड" ("GIZ") द्वारा ग्रांट के माध्यम से स्थापित की गई है।

4) ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन और बैटरी विनिमय के लिए समान शुल्क:

आयोग ने प्रदूषण मुक्त परिवहन और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ई-रिक्शा/ई-वाहन श्रेणी के लिए रियायती टैरिफ दरों को जारी रखने का निर्णय लिया है।

5) डिजिटल दिल्ली:

आयोग मानता है कि कोविड-19 के युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक निर्भरता रखनी होगी। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम भी है। तदनुसार, घरेलू, कृषि और मशरूम की खेती को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल का 20,000/- रुपये से अधिक का भुगतान आवश्यक रूप से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट (जैसे पेटीएम, गूगल पे) आदि के माध्यम से होगा।

- 6) आयोग ने 4,000/- रुपये तक की नकद जमा राशी डिस्कांम्स के काउंटरों पर और 50,000/- रुपये नकद तक के बिजली बिलों का भुगतान नामित निर्धारित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में उपभोक्ताओं द्वारा नकद जमा की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा है।
- 7) सिविल अपील क्रमांक 884/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयोग द्वारा जमा राजस्व अंतर की मूल राशि के क्रमिक परिसमापन के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं पर 8% अतिरिक्त अधिभार की लेवी में कोई बदलाव नहीं किया है।



वित्त वर्ष 2019-20 के सत्यापन और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एआरआर

दिल्ली में बिजली उत्पादन कंपनियां - इन्द्रप्रस्थ पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), पारेषण लाइसेंसधारी - दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) और बिजली वितरण यूटिलिटीज -टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने सकल राजस्व आवश्यकता का सत्यापन (एआरआर) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) वित्त वर्ष 2021-22 के टैरिफ निर्धारण के लिए अपनी याचिकाओं को दायर किया था। याचिकाओं के एडमिशन के बाद, याचिकाओं की कार्यकारी सारांश तैयार किए गए और सभी हितधारकों से प्राप्त सुझाव/सूचनाओं के लिए आयोग की वेबसाइट पर उनकी याचिकाओं के साथ अपलोड किया गया।

- 2) आयोग के द्वारा 15/04/2021, 16/04/2021, 19/04/2021 और 20/04/2021 को वित्त वर्ष 2019-20 के सत्यापन और एआरआर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ याचिकाओं से संबंधित वर्चुअल पब्लिक हियरिंग भी आयोजित की गई।
- 3) दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जीओएनसीटीडी (GoNCTD) ने अपने आदेश संख्या एफ 2/07/2020/पार्ट फ़ाइल III/381 दिनांक 19/04/2021 के तहत कर्फ्यू लगाया, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया और कोविड-19 के कारण विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद पारेषण लाइसेंसधारी अर्थात दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल), वितरण लाइसेंसधारी अर्थात एनडीएमसी, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ने ऐसे कर्फ्यू के प्रभाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की। तदनुसार, सभी हितधारकों को इन बिजली यूटिलिटीज द्वारा दायर अतिरिक्त जानकारी पर टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 29/06/2021 तक अतिरिक्त समय-अवधि दी गई थी।
- 4) वित्त वर्ष 2019-20 के सत्यापन और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एआरआर तथा टैरिफ का विस्तृत आदेश बहुत जल्द जारी किया जाएगा।
- 5) आयोग ने डीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 के विनियम 121(4) के अनुसार पीपीएस-III, बवाना से बिजली के आवंटन को 00:00 बजे 1 अक्टूबर 2021 से 00:00 बजे 31 मार्च 2022 तक निम्नलिखित कारणों के आधार पर संशोधित किया है :

- क) सभी वितरण लाइसेंसधारियों के विभिन्न उपभोक्ता मिश्रण के कारण आवंटित बिजली पोर्टफोलियो की औसत बिजली खरीद लागत और औसत राजस्व के बीच के अंतर को पाटने के लिए ।
- ख) तीस्ता-III से 142 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता के अनुमोदन के लिए एनडीएमसी याचिका आज तक अमल में नहीं आई है । बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) बंद होने के कारण, एनडीएमसी को 125 मेगावाट बिजली का आवंटन बंद कर दिया गया है। अतः महत्वपूर्ण भार वाले अपने वीआईपी क्षेत्र में लोड शेडिंग से बचने के लिए ।

तालिका 1: पीपीएस-III, बवाना का दिल्ली वितरण लाइसेंसधारियों के बीच पुनः आवंटन

पावर प्लांट	बीआरपीएल		बीवाईपीएल		टीपीडीडीएल		एनडीएमसी	
	वर्तमान आवंटन	संशोधित आवंटन	वर्तमान आवंटन	संशोधित आवंटन	वर्तमान आवंटन	संशोधित आवंटन	वर्तमान आवंटन	संशोधित आवंटन
पीपीएस-III, बवाना	38.91%	38.91%	22.50%	19.50%	27.19%	27.19%	9.12%	12.12%



Sr. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES				
1	DOMESTIC						
1.1	INDIVIDUAL CONNECTIONS		0-200	201-400	401-800	801-1200	>1200
Units			Units	Units	Units	Units	
A	Upto 2 kW	20 Rs./kW/month	3.00 Rs./kWh	4.50 Rs./kWh	6.50 Rs./kWh	7.00 Rs./kWh	8.00 Rs./kWh
B	> 2kW and ≤ 5 kW	50 Rs./kW/month					
C	> 5kW and ≤ 15 kW	100 Rs./kW/month					
D	>15kW and ≤ 25 kW	200 Rs./kW/month					
E	> 25kW	250 Rs./kW/month					
1.2	Single Point Delivery Supply for GHS	150 Rs./kW/month	4.50 Rs./kWh				
2	NON-DOMESTIC						
2.1	Upto 3kVA	250 Rs./kVA/month	6.00 Rs./kVAh				
2.2	Above 3kVA	250 Rs./kVA/month	8.50 Rs./kVAh				
3	INDUSTRIAL	250 Rs./kVA/month	7.75 Rs./kVAh				
4	AGRICULTURE	125 Rs./kW/month	1.50 Rs./kWh				
5	MUSHROOM CULTIVATION	200 Rs./kW/month	3.50 Rs./kWh				
6	PUBLIC UTILITIES	250 Rs./kVA/month	6.25 Rs./kVAh				
7	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD. (DIAL)	250 Rs./kVA/month	7.75 Rs./kVAh				
8	ADVERTISEMENT & HOARDINGS	250 Rs./kVA/month	8.50 Rs./kVAh				
9	TEMPORARY SUPPLY						
9.1	Domestic Connections including Group Housing Societies	Same rate as that of relevant category	Same as that of relevant category without any temporary surcharge				
9.2	For threshers during the threshing season	Electricity Tax of MCD : Rs. 270 per connection per month	Flat rate of Rs. 5,400 per month				
9.3	All other connections including construction projects	Same rate as that of the relevant category	1.30 times of the relevant category of tariff				
10	CHARGING STATIONS FOR E-RICKSHAW/E-VEHICLE ON SINGLE POINT DELIVERY/ SWAPPING OF BATTERIES						
10.1	Supply at LT	-	4.50 Rs./kWh				
10.2	Supply at HT	-	4.00 Rs./kVAh				

Notes:

- For Domestic category of consumers, Fixed Charges shall be levied on Sanctioned Load or सस्ते मूल्य पर बिजली की गुणवत्ता, पहुंच और उपलब्धता (24X7) की सुनिश्चिता

Contract Demand as the case may be.

2. For all categories other than Domestic, Fixed Charges are to be levied based on Billing Demand per kW/kVA. Where the Maximum Demand (MD), as defined in *DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017*, reading exceeds sanctioned load/contract demand, a surcharge of 30% shall be levied on the Fixed Charges corresponding to excess load in kW/kVA for such billing cycle only. Wherever, sanctioned Load/Contract Demand is in kW/HP, the kVA shall be calculated on basis of actual Power Factor of the consumer, for the relevant billing cycle and in case of non-availability of actual Power Factor, the Power Factor shall be considered as unity for Sanctioned Load/Contract Demand upto 10kW/11kVA.

3. Time of Day (ToD) Tariff

- a. ToD tariff shall be applicable on all consumers (other than Domestic) whose sanctioned load/MDI (whichever is higher) is 10kW/11kVA and above.
- b. Optional for all other three phase (3 ϕ) connections including Domestic connections. If the consumer who has opted for ToD, the charges for up-gradation of meters, if any, shall be borne by respective consumers.
- c. The Commission has decided to retain the Rebate during the Off Peak hours and Peak hours Surcharge at 20%. Optional ToD Consumers will have the option to move back to non-ToD regime only once within one Financial Year. For other than Peak and Off-Peak hours normal Energy Charges shall be applicable.
- d. The Commission has retained the time slots for Peak and Off-Peak hours as follows:

MONTHS	PEAK HOURS (HRS)	SURCHARGE ON ENERGY CHARGES	OFF-PEAK HOURS (HRS)	REBATE ON ENERGY CHARGES
May - September	1400– 1700 & 2200 – 0100	20%	0400 – 1000	20%

4. Rebate of 3%, 4% & 5% on the Energy Charges for supply at 11kV, 33/66 kV and 220 kV shall be applicable.
5. Maintenance Charges on Street Lights, wherever maintained by DISCOMs, shall be payable @ Rs. 84/light point/month and material cost at the rate of Rs. 19/light point/month as per the Commission's Order dated 22nd September 2009 in addition to the specified tariff. These charges are exclusive of applicable taxes and duties.
6. The valid Factory Licence shall be mandatory for applicability of Tariff under Industrial category:

Provided that in case where the Factory Licence has expired and its renewal application is pending with the concerned authority, the DISCOMs shall bill such consumers as per Tariff applicable under Non Domestic category;

Provided further that on renewal of the Factory Licence, the DISCOMs shall adjust the bills of such consumers as per applicable Tariff under Industrial category from the effective date of renewal of such Licence.

{Explanation – The Factory License for the purpose of applicability of industrial tariff shall mean the license or permission or authorisation or any other document issued or granted by Directorate of Industries or Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises or MCD or any other Central or State Government Agency, as applicable, for running an Industry or Factory in respective field of operation.}

7. The above Tariff Rates shall be subject to following Additional Surcharges to be applied only on the basic Fixed Charges and Energy Charges excluding all other charges e.g., LPSC, Arrears, Electricity Tax/Duty, PPAC, Load Violation Surcharge, etc. for the consumers of BRPL, BYPL & TPDDL:
 - (a) 8% towards recovery of accumulated deficit, and,
 - (b) 7% towards recovery of Pension Trust Charges of erstwhile DVB Employees/ Pensioners as recommended by GoNCTD.
8. The Distribution Licensee shall levy PPAC after considering relevant ToD Rebate/Surcharge on energy charges applicable to the consumers.
9. For consumers availing supply through prepayment meters, the additional rebate of 1% shall be applicable on the basic Energy Charges, Fixed Charges and all other charges on the applicable tariff.
10. The Single Point Delivery Supplier (Group Housing Societies) shall charge the Domestic tariff as per slab rate of 1.1 to its Individual Members availing supply for Domestic purpose and Non Domestic Tariff for other than domestic purpose. Any Deficit/Surplus due to sum total of the billing to the Individual Members as per slab rate of tariff schedule 1.1 and the billing as per the tariff schedule 1.2 including the operational expenses of the Single Point Delivery Supplier shall be passed on to the members of the Group Housing Societies on pro rata basis of consumption.



11. Individual Domestic Consumers availing the supply at single point delivery through Group Housing Society, shall claim the benefit of subsidy, applicable if any, as per the Order of GoNCTD. Group Housing Society shall submit the details of eligible consumers with consumption details and lodge claim of subsidy on behalf of individual members from DISCOMs.
12. The Single Point Delivery Supplier availing supply at HT & above shall charge the tariff to its LT consumers and in addition shall be entitled to charge an extra upto 5% of the bill amount to cover losses and all its expenses.
13. The Commercial Consumers of DMRC and DIAL who have sanctioned load above 215 kVA but served at LT (415 Volts) shall be charged the tariff applicable to Non-domestic LT (NDLT) category greater than 140kW/150kVA (415 Volts).
14. The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity duty and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.
15. In the event of the electricity bill rendered by the Distribution licensee, not being paid in full within the due date specified on the bill, a Late Payment Surcharge (LPSC) @ 18% per annum shall be levied. The LPSC shall be charged for the number of days of delay in receiving payment from the consumer by the Distribution Licensee, until the payment is made in full without prejudice to the right of the licensee to disconnect the supply after due date, in the event of non-payment in accordance with Section 56 of Electricity Act, 2003. This will also apply to temporary connections and enforcement cases, where payment of final bill amount after adjustment of amount as per directions of the Court and deposit, is not made by due date.
16. No payment shall be accepted by the Distribution Licensees from its consumers at its own collection centres/mobile vans in cash towards electricity bill exceeding Rs. 4,000/- except from blind consumers, for court settlement cases & payment deposited by the consumers at designated scheduled commercial bank branches upto Rs. 50,000/-. Violation of this provision shall attract penalty to the level of 10% of total cash collection exceeding the limit.
17. The payment of monthly electricity bills of all categories of consumers except Domestic,



Agriculture & Mushroom Cultivation exceeding Rs. 20,000/- shall be paid Digitally through various platforms like NEFT, RTGS, IMPS, Credit Card, Debit Card, Wallets (like PayTM, Google Pay) etc.

18. Wherever the Fixed or Energy Charges are specified in Rs. per kVAh, for the purpose of billing, the kVAh as read from the meter in the relevant billing cycle shall be used.

DERC

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. DOMESTIC CATEGORY

1.1 Domestic Lighting, Fan and Power (Single Point Delivery and Separate Delivery Points/Meters)

Available to following:

- a. Residential Consumers.
- b. Hostels of recognized/aided institutions which are being funded more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies [local bodies include NDMC and MCDs (North, South & East)].
- c. Staircase lighting in residential flats separately metered.
- d. Compound lighting, lifts and water pumps etc., for drinking water supply and fire-fighting equipment in residential complexes, if separately metered.
- e. In Group Housing Societies etc. for bonafide use of lighting/fan and power, subject to the provision that the supply is at single point delivery for combined lighting/fan & power.
- f. Dispensary/ Hospitals/ Public Libraries/ School/ College/ Working Women's Hostel/ Charitable homes run and funded by more than 90% by Municipal Corporation of Delhi or Government of the NCT of Delhi or any other Government/local bodies.
- g. Small Health Centres including Mohalla Clinics approved by the Department of Health, Government of NCT of Delhi for providing charitable services only.
- h. Recognized Centres for welfare of blind, deaf and dumb, spastic children, physically handicapped persons, mentally retarded persons, as approved by the Government of NCT of Delhi and other Government.
- i. Public parks except temporary use for any other purpose.
- j. Bed and Breakfast Establishments (Residential Premises) registered u/s 3 of the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration & Regulations) Act, 2007.
- k. Places of Worship.
- l. Cheshire homes/Orphanage.
- m. Shelter Homes (including Night Shelters) approved by Delhi Urban Shelter Improvement Board, GoNCTD.
- n. Electric Crematoriums.
- o. Gaushala Registered under GoNCTD.



- p. Professionals i.e. individuals engaged in those activities involving services based on professional skills, viz Doctor, Psychologist, Physiotherapist, Lawyer, Architect, Chartered Accountant, Company Secretary, Cost & Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media Professional and Documentary Film Maker may utilize the domestic connection at their residence for carrying out their professional work in the nature of consultancy without attracting Non-Domestic tariff for the electricity consumed, provided that the area used for professional activity does not exceed the area permitted to be used for such activity in residential area under the Master Plan for Delhi, 2021 (MPD-2021), which as per MPD-2021 is permissible on any one floor only but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR whichever is less on that plot or dwelling unit.
- q. Available, for loads up to 21 kW, to farm houses for bonafide domestic self use.
- r. The consumers (owner, tenant or occupier of premises) running small commercial establishments including Paying Guest from their households (houses under Domestic Category) having sanctioned load upto 5kW under Domestic Category, shall be charged Domestic Tariff.
- s. Cattle Farms/ Dairy Farms/ Dhobi Ghat with a total consumption of not more than 1000 units/month.

1.2 Domestic Connection on Single Point Delivery

Same as 1.1 - For GHS flats and for individuals having sanctioned load above 100 kW/108kVA Group Housing Society (GHS) shall mean a residential complex owned/managed by a Group Housing Society registered with Registrar, Cooperative Societies, Delhi / registered under Societies Act, 1860 and for sake of brevity the definition shall include residential complex developed by a Developer and approved by appropriate authority.

2. NON-DOMESTIC

Available to all consumers for lighting, fan & heating/cooling power appliances in all Non-Domestic establishments as defined below:

- a. Hostels/Schools/Colleges/Paying Guests (other than that covered under Domestic Category)
- b. Auditoriums, Lawyer Chambers in Court Complexes, nursing homes/diagnostic Centres other than those run by Municipal Corporation of Delhi or the Government of NCT of Delhi (other than that covered under domestic category).

- c. Railways (other than traction), Hotels and Restaurants
- d. Cinemas
- e. Banks/Petrol pumps including CNG stations
- f. All other establishments, i.e., shops, chemists, tailors, washing, dyeing, drycleaner, beauty salon, florist, etc. which do not come under the Factories Act.
- g. Fisheries, piggeries, poultry farms, floriculture, horticulture, plant nursery
- h. Farm houses being used for commercial activity
- i. DMRC for its commercial activities other than traction.
- j. DIAL for commercial activities other than aviation activities.
- k. Ice-cream parlours
- l. Single Point Delivery for Commercial Complexes supply at 11 kV or above
- m. Pumping loads of DDA/MCD
- n. Supply to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Ltd. for their on-going construction projects etc. and for commercial purposes other than traction.
- o. Any other category of consumers not specified/covered in any other category in this Schedule.

3. INDUSTRIAL

Available to Industrial consumers & Hospitals (other than that covered in Domestic Category) including lighting, heating and cooling load.

4. AGRICULTURE

Available for load up to 20 kW for tube wells for irrigation, threshing, cultivation and kutti-cutting in conjunction with pumping load for irrigation purposes and lighting load for bonafide use in Kothra.

5. MUSHROOM CULTIVATION

Available for load upto 100 kW for mushroom growing/cultivation.

6. PUBLIC UTILITIES

- a. **DELHI JAL BOARD:** Available to DJB for pumping load & Water Treatment Plants.
- b. **RAILWAY TRACTION:** Available for Indian Railways for Traction Load.



- c. **DELHI METRO RAIL CORPORATION:** Available to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for Traction Load
- d. **PUBLIC LIGHTING:** Street Lighting, Signals & Blinkers
- All street lighting consumers including MCD, DDA, PWD, CPWD, Slums depts., DSIIIDC, MES, GHS etc.
 - Traffic signals and blinkers of Traffic Police
 - Unmetered Public Lighting shall be charged Energy Charge Rate at 1.10 times of applicable Tariff.
7. **DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED:** Available to DIAL for Aviation activities.
8. **ADVERTISEMENT & HOARDINGS:** Electricity for Lighting External Advertisements, External Hoardings and Displays at Departmental Stores, Malls, Multiplexes, Theatres, Clubs, Hotels, Bus Shelters, Railway/Metro Stations, Airport which shall be separately metered and charged at the Tariff applicable for “Advertisements and Hoardings” category, except such displays which are for the purpose of indicating/displaying the name and other details of the shop, commercial premises itself. Such use of electricity shall be covered under the prevailing tariff for such shops or commercial premises.
9. **TEMPORARY SUPPLY**
- a. Available as Temporary Connection under the respective category
 - b. Domestic Tariff without Temporary Surcharge shall be applicable for Religious functions of traditional and established characters like Ramlila, Dussehra, Diwali, Holi, Dandiya, Janmashtami, Nirankari Sant Samagam, Gurupurb, Durga Puja, Eid, Christmas celebrations, Easter, Pageants and cultural activities like NCC camps, scouts & guides camps etc.
10. **CHARGING OF E-RICKSHAW/ E-VEHICLE/ SWAPPING OF BATTERIES**
- a. **Charging Stations for E-Rickshaw/ E-Vehicle on Single Point Delivery:** Available to Charging Stations as per the provisions of *DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017*.
 - b. **Tariff applicable for charging of batteries of E-Rickshaw / E-Vehicle** at premises other than at Charging Stations meant for the purpose shall be the same as applicable for the relevant category of connection at such premises from which the E-Rickshaw / E-Vehicle is being charged.

- ### INTERPRETATION/CLARIFICATION

In case of doubt or anomaly, if any, in the applicability of Tariff or in any other respect, the matter will be referred to the Commission and Commission's decision thereon shall be final and binding.